(ग) जी, हां। निर्माणाधीन दो यूनिट (राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना 3 और 4), जिनमें से प्रत्येक 235 मेगावाट क्षमता का है, के अलावा 4 और यूनिट (राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना 5 से 8 तक), जिनमें से प्रत्येक 500 मेगावाट क्षमता का होगा, उसी स्थल पर लगाए जाएंगे।

(घ) कुल मिलाकर 1230 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाले जो 3 परमाणु बिजलीघर, अर्थात् तारापुर परमाणु बिजलीघर, राजस्थान परमाणु बिजलीघर और मद्रास परमाणु बिजलीघर, इस समय वाणिज्यिक स्तर पर काम कर रहे हैं, उनके प्रचालन और रख-रखाव पर पिछले वित्त वर्ष में लगभग 173.00 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इन तीनों बिजलीघरों ने वर्ष 1988 में 6068 मिलियन यूनिट और वर्ष 1989 में 3984 मिलियन यूनिट बिजली पैदा की थी जिसमें राजस्थान परमाणु बिजलीघर के दोनों यूनिटों का योगदान 1988 तथा 1989 के वर्षों में क्रमशः 1868 मिलियन यूनिट और 1609 मिलियन यूनिट था।

(ङ) हमारे देश में परमाणु बिजलीघरों के प्रचालन से पिछले अनेक वर्षों में मिले अनुभव से यह पता चला है कि इन बिजलीघरों से पर्यावरण में उन्मुक्त होने वाली रेडियोधर्मिता की मात्रा अनुमेय सीमा के भीतर ही रही है तथा उत्पादनरत परमाणु बिजलीघरों के समीप की पर्यावरण सर्वेक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर यह पाया गया है कि पर्यावरण पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

Enquiry against Director, Central Hindi Institute, Agra

943. SHRI N. RAJANGAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any enquiry was instituted in 1981 and again in October, 1986 regarding Financial and Administrative irregularities against the Director, Central Hindi Institute, Agra; if so, what are the details of the charges;

(b) whether it is also a fact that the Committee so constituted had recommended for compulsory reirement of the Director;

(c) whether the Director went to the Court against his transfer to Guwahati; if so, the outcome thereof and the amount spent by the Institution in this regard; and

(d) what action has been taken by Government against the Director?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (PROF. M. G. K. MENON): (a) to (d) In 1981, a departmental Inspection Team was set up to enquire into certain financial and administrative irregularities alleged against the Director, Kendriya Hindi Sansthan (Central Hindi Institute), Agra. On receipt of complaints from various sources, another Enquiry Committee was constituted on 9.10.86 to investigate the complaints of financial and administrative irregularities allegedly committed by the Director of the Sansthan. The complaints investigated by the Inspection Team and the Enquiry Committee related to procedural irregularities in making purchases in the Sansthan, promotion/appointment of staff, unauthorised payments, improper re-appropriation of funds from one head to another, favouritism and partial treatment to certain employees, irregular constitution of Selection Committee/Promotion Committee, harassment of certain employees, misuse of staff cars etc. The Committee has made no recommendation regarding compulsory retirement of the Director.

2. The Head-quarters of Dr. B. G. Misra, Director were transferred to Guwahati in December, 1987 for studying the problems of Hindi teaching in North East. Dr. B. G. Misra, however, filed a writ petition in

Allahabad High Court against these orders. The writ petition was dismissed. According to the information furnished by it, the Kendriya Hindi Sansthan incurred an expenditure of the order of Rs. 2,00,000/- on defending the petitions/Court cases including those filed by Dr. B. G. Misra, during the period from December, 1987 to October, 1989. On submission of report by Dr. B. G. Misra, regarding problems of Hindi Teaching in North East and suggestions to improve the same, his headquarters were transferred back to Agra on 17th November, 1989.

अर्ध-शिक्षित, अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा शिक्षा प्रदान करना

944. **श्री राम नरेश यादव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 मार्च, 1990 के "हिन्दू" में "लिट्रेसी एट दी कास्ट आफ क्वालिटी" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि शिक्षा विभाग के एक कार्यदल ने इस आशय की रिपोर्ट दी है कि देश में बच्चों को अर्ध-शिक्षित और अप्रशिक्षित लोगों द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में तथ्य प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो सरकार कब तक इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेने का विचार रखती है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री साथ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (प्रो० एम० जी० के० मेनन): (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के सम्बन्ध में गठित शिशु-शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा सम्बन्धी कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, पांचवे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित मुद्दों का हवाला दिया है :—

(i) देश में लगभग 12.4% स्कूल शिक्षक अप्रशिक्षित थे ;

(ii) प्राइमरी स्तर पर कार्यरत शिक्षकों में से, लगभग 2.5 लाख (अथवा स्थूल रूप से 13.4%) की मिडिल स्तर अथवा इससे कम स्तर की अर्हता थी । इनमें से लगभग 12.8% भी अप्रशिक्षित थे ।

(iii) मिडिल स्तर पर कार्यरत शिक्षकों में से लगभग 50,000 (अथवा मोटे तौर पर 5.4%) की अर्हता मिडिल अथवा इससे कम थी, और 4.26 लाख (अथवा लगभग 46.3%) की अर्हता हाई स्कूल अथवा इससे कम थी । पहले वर्ग के लगभग 6.4% और बाद के वर्ग के 6.6% अप्रशिक्षित थे ।

(iv) प्राइमरी तथा मिडिल स्तर पर लगभग 36,000 ऐसे शिक्षक थे जिनकी अर्हता मिडिल अथवा इससे कम थी तथा जो अप्रशिक्षित भी थे । इसके अतिरिक्त, मिडिल स्तर पर 24,800 अप्रशिक्षित शिक्षक और थे जिनकी अर्हता हाई-स्कूल थी ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद और कोर्ट की बैठक

945. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1989 और 1990 में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद और कोर्ट की बैठकें किन-किन तारीखों को हुई ; और

(ख) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन दोनों निकायों की बैठकें जल्दी जल्दी हों, क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?